

# Weekly Current Affair

साप्ताहिक करेंट अफेयर्स



(10-16 April 2022)

## Table of Contents

International Relations .....

National.....

State.....

Polity.....

Defense.....

Science & Technology .....

Sports.....

Awards And Honours.....

Appointment/ Resignation.....

Books & Authors.....

Important Days.....



## International Relations

## भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग संरचना 2023-27

## चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, NITI आयोग और संयुक्त राष्ट्र संघ ने आगामी **भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग संरचना (UNSDCF) 2023-27** पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सत्यापन कार्यशाला का आयोजन किया।
- यह ऐसी पहली सभा थी जिसमें 30 केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों, 26 UN एजेन्सियों के प्रमुख तथा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की सहभागिता देखी गई।



## प्रमुख बिंदु

- पिछली भारत सरकार-UNSDCF 2018-22 राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं तथा **सतत विकास लक्ष्यों (SDG)** अर्जित करने के लिए सहयोग, परिणामों तथा कार्यनीतियों की कार्यसूची थी।
- 2018-22 की संरचना NITI आयोग के उपाध्यक्ष तथा संयुक्त राष्ट्र के रेजीडेंट कॉर्डिनेटर इंडिया की अध्यक्षता वाली संयुक्त संचालन समिति द्वारा निर्देशित है जिसमें आर्थिक मामले विभाग तथा विदेश मंत्रालय के सदस्य शामिल हैं।
- 2023-2027 संरचना का उद्देश्य 2030 के एजेंडा के चार स्तंभों - लोग, समृद्धि, ग्रह तथा सहभागिता को भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ समायोजित करना है तथा देश भर में काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र की सभी संस्थाओं के प्रयासों को दिशा उपलब्ध कराना है।
- नई संरचना के छह परिणाम क्षेत्र हैं: (1) स्वास्थ्य एवं कल्याण (2) पोषण एवं भोजन (3) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (4) आर्थिक विकास एवं उत्कृष्ट कार्य (5) पर्यावरण, जलवायु, वाश तथा अनुकूलता (6) लोगों, समुदायों तथा संस्थानों को अधिकार संपन्न बनाना।

स्रोत: PIB

## सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी

## चर्चा में क्यों?

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पंचायती राज संस्थाओं (PRI) की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना-**राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)** को 01 अप्रैल 2022 से 31



मार्च 2026 की अवधि (15वें वित्त आयोग की अवधि) के दौरान कार्यान्वयन जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

## प्रमुख बिंदु

### वित्तीय प्रभाव:

- इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 5,911 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपये है।

### रोजगार सृजन क्षमता सहित प्रमुख प्रभाव:

- RGSA की स्वीकृत योजना देश भर में पारंपरिक निकायों सहित 2.78 लाख से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों को उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर केंद्रित करने के साथ समावेशी स्थानीय शासन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को लेकर काम करने के लिए शासन संबंधी क्षमता विकसित करने में मदद करेगी।

### पृष्ठभूमि:

- तत्कालीन वित्त मंत्री ने 2016-17 के अपने बजट भाषण में, सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थानों की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) की नई पुनर्गठित योजना शुरू करने की घोषणा की।
- इस घोषणा के अनुपालन में और NITI आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति की सिफारिशों के तहत, RGSA की केंद्र प्रायोजित योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21 अप्रैल 2018 को वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक (01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022) लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

### स्रोत: PIB

## प्रधानमंत्री मोदी ने 'प्रधानमंत्री संग्रहालय' का उद्घाटन किया

### चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 'प्रधानमंत्री संग्रहालय' का उद्घाटन किया।



## प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली के तीन मूर्ति एस्टेट में बनाया गया है और इसमें देश के सभी 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों की जीवन यात्रा तथा उनके कार्यों को दर्शाया गया है।
- इसमें 43 गैलरीज हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम और भारत के संविधान के निर्माण पर प्रदर्शित हैं।



स्रोत: TOI

वर्णान्ध (कलर ब्लाइंड) उम्मीदवारों को फिल्म संपादन पाठ्यक्रम का अध्ययन करने की अनुमति दें, सुप्रीम कोर्ट ने FTII को बताया

## चर्चा में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट ने पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (FTII) को निर्देश दिया है कि वह वर्णान्धता (कलर ब्लाइंडनेस) से पीड़ित उम्मीदवारों को फिल्म निर्माण और संपादन पर इसके पाठ्यक्रमों से बाहर न करे और इसके बजाय इसके पाठ्यक्रम में बदलाव करने को कहा।



## प्रमुख बिंदु

### वर्णान्धता (कलर ब्लाइंडनेस):

- कलर ब्लाइंडनेस, जिसे रंग की कमी के रूप में भी जाना जाता है, रंगों को सामान्य तरीके से देखने में असमर्थता है।
- कलर ब्लाइंड व्यक्ति अक्सर कुछ रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं - आमतौर पर हरा और लाल, और कभी-कभी नीला भी।
- रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं प्रकाश का पता लगाती हैं - "छड़", जो प्रकाश और अंधेरे के बीच अंतर करती है, और "शंकु" जो रंग का पता लगाती है।
- तीन प्रकार के शंकु होते हैं जो रंग देखते हैं - लाल, हरा और नीला - और हमारा दिमाग इन कोशिकाओं की जानकारी का उपयोग रंग को देखने के लिए करता है।
- कलर ब्लाइंडनेस इन शंकु कोशिकाओं में से एक या अधिक की अनुपस्थिति या उनके ठीक से काम करने में विफलता का परिणाम हो सकता है।
- कलर ब्लाइंडनेस विभिन्न प्रकार और डिग्री का हो सकता है।

# EXAM PREP



## कारण:

- ज़्यादातर लोगों में वर्णाधता की स्थिति (जन्मजात कलर ब्लाइंडनेस) उनके जन्म के साथ ही होती है। जन्मजात वर्णाधता की स्थिति सामान्यतः आनुवंशिक होती है।
- वर्णाधता की समस्या जो कि जन्म के बाद उत्पन्न होती है, बीमारी, आघात या अंतर्ग्रहण विषाक्त पदार्थों का परिणाम हो सकती है।
- जिन चिकित्सीय स्थितियों से वर्णाधता का खतरा बढ़ सकता है, उनमें ग्लूकोमा, मधुमेह, अल्ज़ाइमर, पार्किंसन, शराब, ल्यूकेमिया और सिकल सेल एनीमिया शामिल हैं।

**नोट:** जून 2020 में भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया था, ताकि हल्के से मध्यम कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सरकार ने देश की अब तक की सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सबका विकास महाक्विज शुरू की

## चर्चा में क्यों?

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन MyGov सबका विकास महाक्विज श्रृंखला का आयोजन कर रहा है, जो नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक आउटरीच प्रयास का हिस्सा है।
- यह प्रश्नोत्तरी 14 अप्रैल 2022 को भारत रत्न डॉ बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उपयुक्त रूप से शुरू की गई है।



## प्रमुख बिंदु

- प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य प्रतिभागियों को विभिन्न योजनाओं और पहलों और लाभों का लाभ उठाने के बारे में जागरूक करना है।
- पहली प्रश्नोत्तरी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) है।

## प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के बारे में:

- PMGKAY एक गरीब समर्थक योजना है जिसका उद्देश्य COVID-19 महामारी के कारण गरीबों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करना है।



- इस योजना के तहत, सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थी हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज के हकदार हैं।
- यह NFSA लाभार्थियों को उपलब्ध अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्नों के अतिरिक्त है।

**स्रोत: न्यूज़ऑनएयर**

## ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022

### चर्चा में क्यों?

- **2022 के लिए ग्लोबल विंड रिपोर्ट** वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद (GWEC) द्वारा प्रकाशित की गई है।



### प्रमुख बिंदु

#### रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने हेतु पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों में वर्ष 2021 के दौरान स्थापित 94 GW (गीगावाट) की पवन ऊर्जा क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष चार गुना बढ़ाने की आवश्यकता है।
- आवश्यक प्रवर्धन के बिना पूर्व-औद्योगिक स्तरों पर ग्लोबल वार्मिंग को पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित लक्ष्य के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना तथा वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।
- वर्ष 2022 में नए अपतटीय प्रतिष्ठानों के वर्ष 2019/2020 के स्तर तक घटने की संभावना है। यह गिरावट मुख्य रूप से चीन में प्रतिष्ठानों की कमी के कारण होगी।
- हालाँकि वर्ष 2023 में बाज़ार में पुनः वृद्धि होने की संभावना है जो अंततः वर्ष 2026 में 30GW के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी।
- यदि अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाया जाता है, तो 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हर साल 0.3-1.61 गीगाटन कम हो सकता है।

#### भारत में दायरा:

- भारत में वर्ष 2021 में 1.4 GW से अधिक पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई जो पिछले वर्ष प्राप्त 1.1 GW की क्षमता से अधिक थी।
- केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 2022 तक 5 GW अपतटीय क्षमता और 2030 तक 30 GW स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। भारत को अभी अपनी अपतटीय पवन ऊर्जा सुविधा विकसित करनी है।
- भारत अपनी 7,600 किमी की तटरेखा के साथ 127 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है।



## संबंधित पहल:

- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति
- राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति

स्रोत: DTE

## भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता

### चर्चा में क्यों?

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ वाशिंगटन डीसी में 11 अप्रैल, 2022 को **चौथी भारत- अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता** में भाग लिया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने संयुक्त राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
- सभी चार उच्च अधिकारी उस समय मौजूद थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन 2+2 वार्ता से पहले 11 अप्रैल को वर्चुअल मिले थे।



### प्रमुख बिंदु

### अमेरिका के साथ वार्ता:

- अमेरिका भारत का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण 2+2 वार्ता साझेदार है।
- दोनों देशों के बीच पहली 2+2 वार्ता ट्रंप प्रशासन के दौरान हुई थी, जब तत्कालीन विदेश मंत्री माइकल पोम्पिओ और तत्कालीन रक्षा सचिव जेम्स मैटिस ने सितंबर 2018 में नई दिल्ली में दिवंगत सुषमा स्वराज और तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी।
- 2+2 संवाद का दूसरा और तीसरा संस्करण क्रमशः 2019 और 2020 में वाशिंगटन डीसी और नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

### रक्षा और सामरिक समझौते:

- भारत और अमेरिका ने 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) से शुरू होकर, पहले 2 + 2 संवाद के बाद 2018 में कम्युनिकेशन कम्पेटिबिलिटी एंड सिक्यूरिटी एग्रीमेंट (COMCASA), और फिर 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) के साथ गहरे सैन्य सहयोग के लिए "मूलभूत समझौते" की एक तिकड़ी पर हस्ताक्षर किए हैं।





## भारत और सहयोगियों के बीच 2+2 वार्ता:

- 2+2 संवाद रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगियों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक का एक प्रारूप है।
- भारत के चार प्रमुख रणनीतिक साझेदारों के साथ 2+2 संवाद हैं: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। रूस के अलावा अन्य तीन देश भी क्वाड में भारत के भागीदार हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## UNGA ने रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के लिए वोट किया

### चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच रूस को मानवाधिकार परिषद (HRC) से निलंबित कर दिया है।



### प्रमुख बिंदु

- 'मानवाधिकार परिषद में रूसी संघ की सदस्यता के अधिकारों का निलंबन' शीर्षक वाले प्रस्ताव को 93 मतों के पक्ष में, 24 के खिलाफ और भारत सहित 58 मतदान नहीं करने के साथ अपनाया गया था।
- इसके साथ, रूस 2006 में स्थापित अधिकार परिषद में सदस्यता अधिकार छीनने वाला दूसरा देश बन गया।
- 2011 में, लीबिया को सभा द्वारा निलंबित कर दिया गया था।

### संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (HRC) के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसका मिशन दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है।

मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड

स्थापना: 15 मार्च 2006

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस



## National

### भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग संरचना 2023-27

#### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, NITI आयोग और संयुक्त राष्ट्र संघ ने आगामी **भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग संरचना (UNSDCF) 2023-27** पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सत्यापन कार्यशाला का आयोजन किया।
- यह ऐसी पहली सभा थी जिसमें 30 केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों, 26 UN एजेन्सियों के प्रमुख तथा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की सहभागिता देखी गई।



#### प्रमुख बिंदु

- पिछली भारत सरकार-UNSDCF 2018-22 राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं तथा **सतत विकास लक्ष्यों (SDG)** अर्जित करने के लिए सहयोग, परिणामों तथा कार्यनीतियों की कार्यसूची थी।
- 2018-22 की संरचना NITI आयोग के उपाध्यक्ष तथा संयुक्त राष्ट्र के रेजीडेंट कॉर्डिनेटर इंडिया की अध्यक्षता वाली संयुक्त संचालन समिति द्वारा निर्देशित है जिसमें आर्थिक मामले विभाग तथा विदेश मंत्रालय के सदस्य शामिल हैं।
- 2023-2027 संरचना का उद्देश्य 2030 के एजेंडा के चार स्तंभों - लोग, समृद्धि, ग्रह तथा सहभागिता को भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ समायोजित करना है तथा देश भर में काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र की सभी संस्थाओं के प्रयासों को दिशा उपलब्ध कराना है।
- नई संरचना के छह परिणाम क्षेत्र हैं: (1) स्वास्थ्य एवं कल्याण (2) पोषण एवं भोजन (3) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (4) आर्थिक विकास एवं उत्कृष्ट कार्य (5) पर्यावरण, जलवायु, वाश तथा अनुकूलता (6) लोगों, समुदायों तथा संस्थानों को अधिकार संपन्न बनाना।

स्रोत: PIB



सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी  
चर्चा में क्यों?

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पंचायती राज संस्थाओं (PRI) की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना-**राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)** को 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि (15वें वित्त आयोग की अवधि) के दौरान कार्यान्वयन जारी रखने की मंजूरी दे दी है।



## प्रमुख बिंदु

### वित्तीय प्रभाव:

- इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 5,911 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपये है।

### रोजगार सृजन क्षमता सहित प्रमुख प्रभाव:

- RGSA की स्वीकृत योजना देश भर में पारंपरिक निकायों सहित 2.78 लाख से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों को उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर केंद्रित करने के साथ समावेशी स्थानीय शासन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को लेकर काम करने के लिए शासन संबंधी क्षमता विकसित करने में मदद करेगी।

### पृष्ठभूमि:

- तत्कालीन वित्त मंत्री ने 2016-17 के अपने बजट भाषण में, सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थानों की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) की नई पुनर्गठित योजना शुरू करने की घोषणा की।
- इस घोषणा के अनुपालन में और NITI आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति की सिफारिशों के तहत, RGSA की केंद्र प्रायोजित योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21 अप्रैल 2018 को वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक (01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022) लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया था।

स्रोत: PIB



## प्रधानमंत्री मोदी ने 'प्रधानमंत्री संग्रहालय' का उद्घाटन किया

### चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 'प्रधानमंत्री संग्रहालय' का उद्घाटन किया।

### प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली के तीन मूर्ति एस्टेट में बनाया गया है और इसमें देश के सभी 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों की जीवन यात्रा तथा उनके कार्यों को दर्शाया गया है।
- इसमें 43 गैलरीज हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम और भारत के संविधान के निर्माण पर प्रदर्शित हैं।



स्रोत: TOI

## वर्णान्ध (कलर ब्लाइंड) उम्मीदवारों को फिल्म संपादन पाठ्यक्रम का अध्ययन करने की अनुमति दें, सुप्रीम कोर्ट ने FTII को बताया

### चर्चा में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट ने पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (FTII) को निर्देश दिया है कि वह वर्णांधता (कलर ब्लाइंडनेस) से पीड़ित उम्मीदवारों को फिल्म निर्माण और संपादन पर इसके पाठ्यक्रमों से बाहर न करे और इसके बजाय इसके पाठ्यक्रम में बदलाव करने को कहा।



### प्रमुख बिंदु

#### वर्णांधता (कलर ब्लाइंडनेस):

- कलर ब्लाइंडनेस, जिसे रंग की कमी के रूप में भी जाना जाता है, रंगों को सामान्य तरीके से देखने में असमर्थता है।
- कलर ब्लाइंड व्यक्ति अक्सर कुछ रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं - आमतौर पर हरा और लाल, और कभी-कभी नीला भी।
- रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं प्रकाश का पता लगाती हैं - "छड़", जो प्रकाश और अंधेरे के बीच अंतर करती है, और "शंकु" जो रंग का पता लगाती है।



- तीन प्रकार के शंकु होते हैं जो रंग देखते हैं - लाल, हरा और नीला - और हमारा दिमाग इन कोशिकाओं की जानकारी का उपयोग रंग को देखने के लिए करता है।
- कलर ब्लाइंडनेस इन शंकु कोशिकाओं में से एक या अधिक की अनुपस्थिति या उनके ठीक से काम करने में विफलता का परिणाम हो सकता है।
- कलर ब्लाइंडनेस विभिन्न प्रकार और डिग्री का हो सकता है।

## कारण:

- ज़्यादातर लोगों में वर्णांधता की स्थिति (जन्मजात कलर ब्लाइंडनेस) उनके जन्म के साथ ही होती है। जन्मजात वर्णांधता की स्थिति सामान्यतः आनुवंशिक होती है।
- वर्णांधता की समस्या जो कि जन्म के बाद उत्पन्न होती है, बीमारी, आघात या अंतर्ग्रहण विषाक्त पदार्थों का परिणाम हो सकती है।
- जिन चिकित्सीय स्थितियों से वर्णांधता का खतरा बढ़ सकता है, उनमें ग्लूकोमा, मधुमेह, अल्ज़ाइमर, पार्किंसन, शराब, ल्यूकेमिया और सिकल सेल एनीमिया शामिल हैं।

**नोट:** जून 2020 में भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया था, ताकि हल्के से मध्यम कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

**स्रोत:** इंडियन एक्सप्रेस

सरकार ने देश की अब तक की सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सबका विकास महाक्विज शुरू की

## चर्चा में क्यों?

- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन MyGov सबका विकास महाक्विज श्रृंखला का आयोजन कर रहा है, जो नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक आउटरीच प्रयास का हिस्सा है।
- यह प्रश्नोत्तरी 14 अप्रैल 2022 को भारत रत्न डॉ बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उपयुक्त रूप से शुरू की गई है।



## प्रमुख बिंदु

- प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य प्रतिभागियों को विभिन्न योजनाओं और पहलों और लाभों का लाभ उठाने के बारे में जागरूक करना है।



- पहली प्रश्नोत्तरी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)** है।

## प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के बारे में:

- PMGKAY एक गरीब समर्थक योजना है जिसका उद्देश्य COVID-19 महामारी के कारण गरीबों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करना है।
- इस योजना के तहत, सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थी हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज के हकदार हैं।
- यह NFSA लाभार्थियों को उपलब्ध अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्नों के अतिरिक्त है।

## स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

## भारत ने नेबरहुड आउटरीच पर पहला विदेश मंत्रालय के नेतृत्व वाला अंतर-मंत्रालयी समन्वय समूह बनाया

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला द्वारा भारत के नेबरहुड आउटरीच पर **अंतर-मंत्रालयी समन्वय समूह (IMCG)** की पहली बैठक बुलाई गई थी।



### प्रमुख बिंदु

- बैठक का केंद्र बिंदु सीमा अवसंरचना का निर्माण था जो नेपाल जैसे पड़ोसियों के साथ अधिक व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा; आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में भूटान और मालदीव जैसे देशों की विशेष जरूरतें; बांग्लादेश के साथ रेल संपर्क खोलना; अफगानिस्तान और म्यांमार को मानवीय सहायता; और श्रीलंका के साथ मत्स्य पालन का मुद्दा।

## अंतर-मंत्रालयी समन्वय समूह (IMCG) के बारे में:

- IMCG को विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिवों द्वारा बुलाई गई अंतर-मंत्रालयी संयुक्त कार्यबल (JTFs) द्वारा समर्थित किया जाता है।
- "**नेबरहुड फर्स्ट**" नीति के तहत अधिक से अधिक संपर्क, मजबूत अंतर-संपर्क और लोगों से लोगों के बीच अधिक से अधिक जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल है।



स्रोत: ET

## 'स्वनिधि से समृद्धि' योजना

### चर्चा में क्यों?

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के सचिव मनोज जोशी ने 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में 'स्वनिधि से समृद्धि' योजना का शुभारंभ किया।



### प्रमुख बिंदु

#### 'स्वनिधि से समृद्धि' योजना के बारे में:

- 'स्वनिधि से समृद्धि', पीएमस्वनिधि की एक अतिरिक्त योजना है जो 4 जनवरी 2021 को चरण-1 में 125 शहरों में शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार को शामिल किया था।
- चरण-1 की सफलता को ध्यान में रखते हुए MoHUA ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल 20 लाख योजना स्वीकृतियों के लक्ष्य के साथ 28 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवारों को कवर करने के उद्देश्य से देश के अतिरिक्त 126 शहरों में इस योजना का विस्तार शुरू किया है।

#### पीएमस्वनिधि (PMSVANidhi) योजना के बारे में:

- MoHUA 1 जून 2020 से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू कर रहा है।
- इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दर और आसान शर्तों पर काम करने के लिए पूंजी ऋण प्रदान करना है। इस योजना ने सफलतापूर्वक 30 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंचाया है।
- कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार की 8 कल्याणकारी योजनाओं के लिए उनकी पात्रता का आकलन करने और पात्र योजनाओं की मंजूरी के लिए पीएमस्वनिधि लाभार्थियों और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग की जाती है।
- इन योजनाओं में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम (BOCW), प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) पोर्टेबिलिटी लाभ-एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC), जननी सुरक्षा योजना, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत पंजीकरण शामिल हैं।
- इस योजना के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) कार्यान्वयन भागीदार है।



स्रोत: PIB

11 वर्षों में पहली बार, घरेलू पेटेंट दायर किए जाने की संख्या भारत में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग की संख्या से अधिक हुई

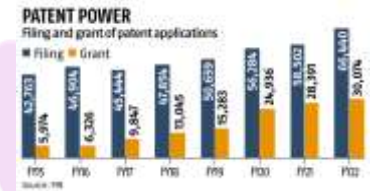
चर्चा में क्यों?

- भारत ने IP नवोन्मेषण परितंत्र के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित कर ली है जिसमें 11 वर्षों में पहली बार, जनवरी-मार्च 2022 के दौरान घरेलू पेटेंट दायर किए जाने की संख्या भारत में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग की संख्या से अधिक हो गई, अर्थात दायर किए गए कुल 19796 पेटेंट आवेदनों में से भारतीय आवेदकों द्वारा 10706 पेटेंट आवेदन दायर किए गए जबकि गैर भारतीयों ने 9090 आवेदन दायर किए।



प्रमुख बिंदु

- पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों ने भारत की IP व्यवस्था को मजबूत बनाया है जिसमें ऑनलाइन फाइलिंग पर 10 प्रतिशत की छूट, स्टार्ट-अप्स, छोटी संस्थाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों के लिए 80 प्रतिशत शुल्क रियायत तथा अन्य वर्गों के साथ साथ स्टार्ट-अप्स, और MSME के लिए त्वरित परीक्षा के प्रावधान शामिल हैं।
- यह भारत को वैश्विक नवोन्मेषण सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में शामिल होने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के एक कदम और निकट ले जाएगा।



राष्ट्रीय IPR नीति द्वारा निर्धारित आधारशिला तथा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की बदौलत भारत ने निम्नलिखित उपलब्धियां अर्जित करने में सफलता प्राप्त की है:

- पेटेंट दायर करने की संख्या वित्त वर्ष 2014-15 के 42763 से बढ़ कर वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 66440 तक पहुंच गई जो सात वर्षों की अवधि में 50 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है
- वित्त वर्ष 2014-15 (5978) की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 (30,074) में पेटेंट प्रदान किए जाने की संख्या में लगभग पांच गुनी बढ़ोतरी हुई
- विभिन्न प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों के लिए पेटेंट की जांच के समय में कमी जिसमें 2016 के दौरान 72 महीनों का समय लगता था जबकि अब 5 से 23 महीनों तक का समय लगता है
- वैश्विक नवोन्मेषण सूचकांक में भारत की रैंकिंग वित्त वर्ष 2015-16 के 81वें स्थान की तुलना में बेहतर होकर 2021 के दौरान 46वें स्थान पर आ गई (35 स्थान ऊपर)

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड





## 5G वर्टिकल एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम (VEPP)

### चर्चा में क्यों?

- दूरसंचार विभाग (DoT) ने "5G वर्टिकल एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम (VEPP)" पहल के लिए एक्सप्रेसन ऑफ इंटररेस्ट (EoI) आमंत्रित किया है, जिसमें 5G यूज-केस इकोसिस्टम हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग साझेदारी के तेजी से निर्माण करने तथा विशेषकर उपयोगकर्ता / वर्टिकल उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष जोर दिया गया है।



### प्रमुख बिंदु

- सचिव (दूरसंचार) के मार्गदर्शन में, उपयोग कार्यक्षेत्र (यूसेज वर्टिकल) में 5G अवसरों को कई गुना करने के लिए, सदस्य (प्रौद्योगिकी), डिजिटल संचार आयोग की अध्यक्षता में एक **अंतर-मंत्रालयी समिति** का गठन इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रासंगिक कार्यक्षेत्र के मंत्रालय अर्थात कृषि, स्वास्थ्य, शहरी मामले, शिक्षा, बिजली, खान, जलशक्ति, वाणिज्य, पत्तन, रेलवे, भारी उद्योग, सड़क परिवहन, पर्यटन आदि के प्रतिनिधियों के साथ हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है।
- "5G वर्टिकल एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम" को उद्योग वर्टिकल के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें उपयोगकर्ता वर्टिकल और 5G टेक हितधारकों (सेवा प्रदाताओं, समाधान प्रदाताओं और भागीदार OEM) के बीच घनिष्ठ सहयोग को सक्षम करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेसन ऑफ़ इंटररेस्ट - EoI) के माध्यम से अभिनव 5G उपयोग के मामलों के परीक्षण सह उत्पादन आधार (टेस्टिंग -कम- ब्रीडिंग ग्राउंड) के रूप में क्षमता है।

### 5G प्रौद्योगिकी के बारे में:

- 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है।
- यह 1G, 2G, 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है।
- 5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति 20 Gbps (गीगाबिट प्रति सेकंड) जितनी अधिक होने का परीक्षण किया गया है।

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**



## उत्सव पोर्टल

### चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में 12 से 13 अप्रैल तक आयोजित होने वाले **अमृत समागम** के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
- 2 दिवसीय अमृत समागम सम्मेलन के उद्घाटन दिवस के दौरान, जी किशन रेड्डी ने **उत्सव पोर्टल** का भी शुभारंभ किया।



### प्रमुख बिंदु

- उत्सव पोर्टल वेबसाइट, पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल, का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों को दुनिया भर में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में सभी कार्यक्रमों, त्योहारों और लाइव दर्शन को प्रदर्शित करना है।

### नोट:

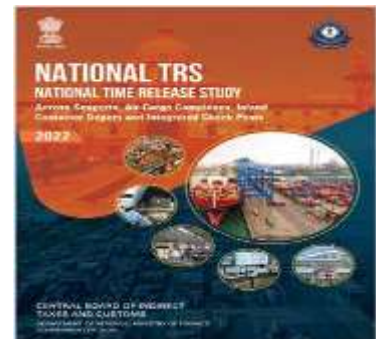
- मंत्रालय ने **25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस** के अवसर पर AKAM (आजादी का अमृत महोत्सव) पर समर्पित पर्यटक स्थलों की थीम पर एक डिजिटल कैलेंडर भी जारी किया था।
- मंत्रालय ने **PRASHAD योजना** के तहत पहचाने गए तीर्थ और विरासत स्थलों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से, 2021-22 के दौरान कुल 112.25 करोड़ रुपये की 03 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- मंत्रालय ने हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना को **स्वदेश दर्शन 2.0** के रूप में नया रूप दिया है।

### स्रोत: PIB

## नेशनल टाइम रिलीज स्टडी, 2022

### चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने **नेशनल टाइम रिलीज स्टडी (NTRS), 2022** जारी किया।



## प्रमुख बिंदु

- NTRS 2022 अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कार्गो निकासी प्रक्रिया का आकलन करने के लिए एक प्रदर्शन माप उपकरण है, जैसा कि व्यापार सुविधा समझौते (TFA) और विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO) के तहत विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा अनुशंसित है।
- NTRS ने 15 प्रमुख सीमा शुल्क संरचनाओं को कवर किया, जिसमें चार बंदरगाह श्रेणियां - बंदरगाह, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (ACC), अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD) और एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) शामिल हैं, जो लगभग 80 प्रतिशत बिल ऑफ एंट्री (आयात दस्तावेज) को और शिपिंग बिलों का 70 प्रतिशत (निर्यात दस्तावेज) संभालते हैं।
- NTRS 2022 ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2022 में सभी चार बंदरगाह श्रेणियों के लिए औसत कार्गो रिलीज समय में और सुधार की सूचना दी है: ICP के लिए 2 प्रतिशत से ACC के लिए काफी अधिक 16 प्रतिशत। समुद्री बंदरगाह या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के माध्यम से साफ किए गए समुद्री कार्गो के लिए औसत रिलीज समय में 12 प्रतिशत का सुधार हुआ है।
- इस सुधार के साथ, ICP ने राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (NTFAP) लक्ष्य रिलीज समय को 2023 तक हासिल कर लिया है, जबकि अन्य तीन बंदरगाह श्रेणियां NTFAP लक्ष्य के 75 प्रतिशत तक पहुंच गई हैं।

स्रोत: PIB

## राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड-1

## चर्चा में क्यों?

- NITI आयोग ने 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक (SECI) -राउंड 1 का शुभारंभ किया।

Score and Ranking of Larger States								
Rank	States/UTs	DISCOM's Performance	Access, affordability & reliability	Clean Energy initiatives	Energy efficiency	Env Sustainability	New initiatives	SECI score
1	Gujarat	72.7	52.4	59.2	40.1	33.1	5.5	50.1
2	Kerala	64.4	67.9	23.5	38	46.9	7.7	48.1
3	Punjab	77.1	46.8	26.1	33.1	37	2.1	48.5
4	Haryana	69.8	53.6	42.9	31.7	33.6	5.9	47.8
5	Uttarakhand	61.9	55.3	16.3	30.3	48.7	14.7	46.3
6	Madhya Pradesh	67.7	51.2	34	25.7	36.2	10.4	46.0
7	Himachal Pradesh	57	36.3	14.3	20.1	32.1	38.1	45.4
8	Karnataka	56.8	45.5	27	37.2	41.7	14.5	43.8
9	Tamil Nadu	57.3	46.3	21.7	35.4	39.2	4	43.4
10	Assam	67.3	38.3	4.3	39	39.9	17.6	42.6
11	Telangana	55.1	60.4	18	64.7	34.6	0.4	41.9
12	Andhra Pradesh	65.1	42.6	16.9	40	35	0	41.6
13	Uttar Pradesh	59.9	37.9	12.6	42	30.9	27.4	41.0
14	West Bengal	55.3	52	8.5	27.7	40.9	9	38.9
15	Bihar	61.3	45	4.9	32.8	33.7	7.6	38.3
16	Odisha	59.0	57.4	-4.8	21.8	22.6	0.9	37.1
17	Rajasthan	49.2	42.9	15.5	44	31.4	4.8	35.4
18	Jharkhand	58.3	46.5	2.9	17.2	19	9.3	35.2
19	Madhya Pradesh	53.7	42.7	6.2	8.3	24.1	3.3	32.6
20	Chhattisgarh	58.4	45.4	2.1	0	5.8	4.2	31.7



## प्रमुख बिंदु

- गुजरात, केरल और पंजाब को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष तीन प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में स्थान दिया गया है।
- गोवा, छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है, इसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर का स्थान है।
- केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव/दादरा और नगर हवेली शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं।
- ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक राउंड-1 ऊर्जा क्षेत्र के बारे में राज्यों के साथ बातचीत शुरू करने में मदद करेगा ताकि आवश्यक नीतिगत सुधार किए जा सकें।
- राज्य, ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड-1 में राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों में कार्य प्रदर्शन अर्थात् (1) डिस्कॉम का प्रदर्शन (2) ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता (3) स्वच्छ ऊर्जा पहल (4) ऊर्जा दक्षता (5) पर्यावरण में स्थिरता और (6) नई पहल, के आधार पर रैंक दिया गया है।
- इन मापदंडों को आगे 27 संकेतकों में विभाजित किया गया है। समग्र SECI राउंड-1 स्कोर के आधार पर, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तीन समूहों फ्रंट रनर, अचीवर्स और एस्पिरेंट्स में वर्गीकृत किया गया है।
- राज्यों को आकार और भौगोलिक अंतर के आधार पर बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Score and ranking of Smaller States								
Rank	States/UTs	DISCOM's Performance	Access, affordability & reliability	Clean Energy Initiatives	Energy Efficiency	Env Sustainability	New Initiatives	SECI score
1	Goa	65.4	59.6	62.4	16.6	43.7	12.4	51.4
2	Tripura	57.3	33.1	22.9	31.7	39.6	58.7	45.0
3	Manipur	57.6	34.1	4.7	22.1	41.3	7.3	36.0
4	Mizoram	51.7	39.3	18.9	29.7	38.2	1.1	35.9

Score and ranking of Union Territories								
Rank	States/UTs	DISCOM's Performance	Access, affordability & reliability	Clean Energy Initiatives	Energy Efficiency	Env Sustainability	New Initiatives	SECI score
1	Chandigarh	65.6	58.7	89.2	16.2	62.5	14.1	55.7
2	Delhi	66.2	38.3	67.2	43.9	38.6	49.7	55.6
3	D&D and D&N	71.5	60.3	68.6	0	36	7.9	53.2
4	Puducherry	67.9	57.7	20.3	0.6	42.7	37.9	48.5
5	A&N	37.7	35	20.6	1.3	49.5	0	29.4
6	J&K*	31.2	51.4	11.6	9.9	51.8	4.5	29.3
7	Lakshadweep	42.9	25.9	33.6	0	7.1	0	26.9

स्रोत: PIB

## UIDAI तथा ISRO ने तकनीकी सहयोग के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए

## चर्चा में क्यों?

- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) तथा हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय रिमोट



**सेंसिंग सेंटर (NRSC), ISRO** के बीच तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

## प्रमुख बिंदु

- NRSC देश भर में फैले आधार केंद्रों के बारे में जानकारी तथा स्थानों की सूचना प्रदान करते हुए भुवन-आधार पोर्टल का विकास करेगा।
- NRSC नियमित वैधानिक निरीक्षण करने के द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं में सुधार लाने के लिए विद्यमान तथा नए नामांकन केंद्रों से संबंधित डाटा एकत्र करने और संग्रहित करने के लिए वेब आधारित पोर्टल भी उपलब्ध कराएगा।
- भुवन प्राकृतिक रंग उपग्रह छवियों के हाई रिजोलुशन पृष्ठभूमि के साथ आधार केंद्रों के लिए पूर्ण भौगोलिक सूचना भंडारण, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण तथा रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

## भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के बारे में:

- UIDAI भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत 12 जुलाई, 2016 को आधार (वित्तीय तथा अन्य सब्सिडी, लाभों तथा सेवाओं की लक्षित प्रदायगी) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम, 2016) के प्रावधानों के तहत स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण है।
- UIDAI ने अभी तक 132 करोड़ से अधिक निवासियों को आधार संख्या जारी की हैं।

स्रोत: PIB

**NTCA की बैठक पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर अरुणाचल प्रदेश में हुई**

## चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाघ अभयारण्य में **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** की 20वीं बैठक आयोजित की गई।
- NTCA के इतिहास में पहली बार इसकी बैठक राष्ट्रीय राजधानी से बाहर हुई।



## प्रमुख बिंदु

- NTCA ने पुनरुत्पादन और पूरकता से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रोटोकॉल (SOP) तैयार किया है।



- बाघ अभयारण्यों के प्रबंधकों को आग से निपटने की उनकी तैयारियों का आकलन करने और जंगल में लगने वाली आग के संपूर्ण जीवन चक्र का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए, NTCA ने बाघ अभयारण्यों के लिए फारेस्ट फायर ऑडिट प्रोटोकॉल तैयार किया है।
- समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर NTCA द्वारा भारत में टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (MEE) पर तकनीकी मैनुअल जारी किया जा रहा है।
- भारत के जंगलों में दुनिया के लगभग 70 प्रतिशत बाघ रहते हैं।

## राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के बारे में:

- NTCA की स्थापना दिसंबर 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद की गई थी, जिसका गठन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर और भारत में कई टाइगर रिजर्व के पुनर्गठित प्रबंधन के लिए किया गया था।
- WWF के सहयोग से भारत सरकार द्वारा 1973 में 'टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम' (जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है) नामक संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था।

## स्रोत: PIB

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) संवर्धन टास्क फोर्स का गठन किया

## चर्चा में क्यों?

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) संवर्धन टास्क फोर्स का गठन किया।



## प्रमुख बिंदु

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव AVGC संवर्धन टास्क फोर्स के प्रमुख होंगे।
- AVGC संवर्धन टास्क फोर्स 90 दिनों के भीतर अपनी पहली कार्य योजना प्रस्तुत करेगा।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में देश में AVGC क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
- भारत के पास एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र में "क्रिएट इन इंडिया" और "ब्रांड इंडिया" के तहत अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता है।
- भारत के पास इस क्षेत्र में लगभग 25-30 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि और सालाना 1,60,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित करने के साथ वर्ष 2025 तक वैश्विक बाजार की 5 प्रतिशत हिस्सेदारी (लगभग 40 बिलियन डॉलर) हासिल करने की क्षमता है।



स्रोत: द हिंदू

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन के विस्तार को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने **अटल इनोवेशन मिशन (AIM)** को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।



प्रमुख बिंदु

**AIM द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अभीष्ट लक्ष्य हैं:**

- 10,000 अटल टिकरिंग लैब (ATL) की स्थापना करना
- 101 अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AIC) की स्थापना करना
- 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (ACIC) की स्थापना करना
- अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज के माध्यम से 200 स्टार्टअप को सहायता प्रदान करना
- उपरोक्त सेंटरों की स्थापना और लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने की इस प्रक्रिया में कुल 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का निर्धारित बजट खर्च किया जाएगा।

**अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के बारे में:**

- अटल इनोवेशन मिशन को वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2015 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप NITI आयोग के तहत स्थापित किया गया है।
- AIM का मुख्य उद्देश्य स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) और उद्योगों के स्तरों पर विभिन्न उपायों के माध्यम से देश भर में नवाचार और उद्यमिता का एक इकोसिस्टम बनाना और उसे बढ़ावा देना है।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड



केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों (UT) में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS), समेकित बाल विकास सेवा (ICDS), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण-PM पोषण [पूर्ववर्ती मध्याह्न भोजन योजना (MDM)] और भारत सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं (OWS) में 2024 तक चरणबद्ध रूप से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।



प्रमुख बिंदु

- चावल के फोर्टिफिकेशन की पूरी लागत (लगभग 2,700 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) जून, 2024 तक इसके पूर्ण कार्यान्वयन होने तक खाद्य सब्सेडी के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
- भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य की एजेंसियां पहले से ही फोर्टिफाइड चावल की खरीद में लगे हुए हैं और अब तक आपूर्ति एवं वितरण के लिए लगभग 88.65 LMT फोर्टिफाइड चावल की खरीद की जा चुकी है।
- इससे पहले, 2019-20 से "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन और इसका वितरण" पर केंद्र प्रायोजित प्रायोगिक योजना को 3 साल की अवधि के लिए लागू किया गया था।
- ग्यारह राज्यों - आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड ने प्रायोगिक योजना के तहत अपने चिन्हित जिलों (प्रति राज्य एक जिला) में फोर्टिफाइड चावल का सफलतापूर्वक वितरण किया।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस





## 'अवसर' योजना

### चर्चा में क्यों?

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने 'अवसर' योजना के माध्यम से अपने हवाईअड्डों पर स्वयं सहायता समूहों (SHG) को अपने क्षेत्र के स्व-निर्मित उत्पादों की बिक्री/प्रदर्शित करने के लिए स्थान आवंटित करने की पहल की है।



### प्रमुख बिंदु

"अवसर" (क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाईअड्डा) योजना के बारे में:

- "अवसर" योजना के तहत आत्मनिर्भरता के लिए अपने परिवारों को कार्यात्मक रूप से प्रभावी स्व-अर्जित समूहों में संगठित करने में जरूरतमंदों की सहायता करने का मौका प्रदान किया गया है।
- इस योजना के तहत AAI संचालित हर एक हवाई अड्डे पर 100-200 वर्ग फीट का क्षेत्र निर्धारित किया गया है।
- स्वयं सहायता समूहों को एक-एक कर 15 दिनों की अवधि के लिए यह स्थान आवंटित किया जा रहा है।
- चेन्नई, अगरतला, देहरादून, कुशीनगर, उदयपुर और अमृतसर हवाईअड्डे पर कुछ आउटलेट पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। इन आउटलेटों पर हवाई यात्रियों को स्थानीय महिलाओं की SHG अपने घर के बने स्थानीय उत्पादों जैसे, मुरमुरे, डिब्बाबंद पापड़, अचार, बांस आधारित लेडीज बैग/बोतल/लैप सेट, स्थानीय कलाकृतियां, पारंपरिक शिल्प, प्राकृतिक रंग, कढ़ाई और मौजूदा डिजाइन के साथ स्वदेशी बुनाई का प्रदर्शन और विपणन कर रहे हैं।

स्रोत: PIB

State

मुंबई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा '2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड' के रूप में मान्यता दी गई



## चर्चा में क्यों?

- आर्बर डे फाउंडेशन के साथ संयुक्त राष्ट्र (UN) के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा मुंबई को '2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड' के रूप में मान्यता दी गई है।



## प्रमुख बिंदु

- मुंबई को "स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी पेड़ों और हरियाली को उगाने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता" के लिए मान्यता मिली।
- मुंबई यह सम्मान पाने वाला भारत का दूसरा शहर है।
- इससे पहले, हैदराबाद यह सम्मान पाने वाला भारत का एकमात्र शहर था।
- संयुक्त राष्ट्र का 'ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड' कार्यक्रम अपने शहरी वन के प्रति समुदायों के समर्पण के लिए दिशा, सहायता और विश्वव्यापी मान्यता प्रदान करता है, और एक स्वस्थ, टिकाऊ शहरी वानिकी के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## Polity

कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीति

## चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 [CBA अधिनियम] के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीति को मंजूरी दी है।



## प्रमुख बिंदु

- इस नीति में कोयला और ऊर्जा से संबंधित अवसंरचना के विकास तथा स्थापना के उद्देश्य से ऐसी भूमि के उपयोग का प्रावधान है।
- CBA अधिनियम में किसी भी ऋणभार से मुक्त, कोयला युक्त भूमि के अधिग्रहण और इसे सरकारी कंपनी में निहित करने का प्रावधान है।



## Weekly Current Affairs

- अनुमोदित नीति, CBA अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के निम्न प्रकार के उपयोग के लिए स्पष्ट नीतिगत रूपरेखा प्रदान करती है: कोयला खनन गतिविधियों के लिए भूमि; अब उपयुक्त नहीं है या आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है; या जिन भू-क्षेत्रों से कोयले का खनन/कोयला निकालने का कार्य हो चुका है और ऐसी भूमि को फिर से प्राप्त किया गया है।
- सरकारी कोयला कंपनियां, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और इसकी सहायक कंपनियां, CBA अधिनियम के तहत अधिग्रहित इन भू-क्षेत्रों की मालिक बनी रहेंगी और यह नीति, केवल नीति में दिए गए निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए ही, भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति देती है।

### कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957:

- **CBA अधिनियम, 1957** में कोयले के भंडार वाली या संभावित भूमि के अधिग्रहण और उससे जुड़े मामलों का प्रावधान है।
- अन्य आवश्यकताओं के लिए, जैसे स्थायी अवसंरचना, कार्यालय, निवास आदि के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है।

स्रोत: HT

## Defense

### भारत-ऑस्ट्रेलिया समुद्री पेट्रोल टोही विमान (MPRA) का समन्वित संचालन

#### चर्चा में क्यों?

- भारतीय नौसेना का एक **P8I समुद्री पेट्रोल और टोही विमान (MPRA)** ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंच गया है।

#### प्रमुख बिंदु

- विमान और उसके चालक दल डार्विन में एक समन्वित संचालन को अंजाम देंगे।
- अपने प्रवास के दौरान, भारतीय नौसेना की समुद्री पेट्रोल स्क्वाड्रन, अल्बार्ट्रास का दल और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना के 92 विंग के अपने समकक्षों के साथ संचालन करेंगे।
- दोनों देशों के P8 विमान, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह निगरानी के लिए एक साथ अभ्यास का संचालन करेंगे।



## Weekly Current Affairs

- P8 विमान ने अपनी लंबी दूरी की पहुंच के साथ, **मालाबार और AUSINDEX श्रृंखला अभ्यासों** के दौरान संयुक्त रूप से संचालन करते हुए अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है, और संचालन प्रक्रियाओं और सूचनाओं को साझा करने में एक समान भूमिका निभाई है।

स्रोत: इंडिया टुडे

**टैंक रोधी मार्गदर्शित मिसाइल 'हेलीना' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया**

**चर्चा में क्यों?**

- स्वदेश में ही विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली **टैंक-रोधी मार्गदर्शित मिसाइल (ATGM) 'हेलीना'** का पोखरण में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।



**प्रमुख बिंदु**

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना की वैज्ञानिकों की टीमों द्वारा यह परीक्षण संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
- ये परीक्षण एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH) से किए गए थे और मिसाइल को नकली टैंक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक दागा गया।
- हेलीना की अधिकतम सीमा सात किलोमीटर है और इसे ALH के हथियारयुक्त संस्करणों पर एकीकरण के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है।
- हेलीना को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला (DRDL), हैदराबाद द्वारा DRDO के मिसाइल और सामरिक प्रणाली (MSS) क्लस्टर के तहत विकसित किया गया है। 2018 से मिसाइल का सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किया गया है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस



## Weekly Current Affairs

पिनाका Mk-I (और अधिक खूबियों के साथ) रॉकेट प्रणाली तथा पिनाका एरिया डेनियल म्यूनिशन रॉकेट प्रणाली का DRDO और भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया

चर्चा में क्यों?

- पिनाका Mk- I (और अधिक खूबियों के साथ) रॉकेट प्रणाली (EPRS) तथा पिनाका एरिया डेनियल मुनिशन (ADM) रॉकेट प्रणाली का पोखरण फायरिंग रेंज में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।



### प्रमुख बिंदु

- पिनाका रॉकेट प्रणाली को पुणे की आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है, जिसे DRDO के पुणे स्थित एक अन्य संस्थान उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया गया है।
- EPRS रॉकेट प्रणाली का उन्नत संस्करण है, जो पिछले एक दशक से भारतीय सेना के साथ सेवा में है।
- उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रणाली को उच्च श्रेणी की प्रौद्योगिकियों के साथ उन्नत किया गया है।

### नोट:

- इससे पहले, DRDO ने ओडिशा तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) में **सॉलिड फ्यूज डक्टेड रैमजेट (SFDR)** बूस्टर तकनीक का सफल परीक्षण किया गया।
- रक्षा उत्पादन से संबंधित इकोसिस्टम में निजी उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को जारी रखते हुए, रक्षा मंत्रालय ने अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान घरेलू निजी उद्योग के लिए घरेलू पूंजीगत खरीद / अधिग्रहण संबंधी बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा यानी 21,149.47 करोड़ रुपये निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

स्रोत: PIB



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की

चर्चा में क्यों?

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रमुख उपकरण/प्लेटफॉर्म वाली **101 वस्तुओं की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची** जारी की।
- यह पहली सूची (101) और दूसरी सूची (108) पर आधारित है जिसे क्रमशः 21 अगस्त, 2020 और 31 मई, 2021 को जारी किया गया था।



प्रमुख बिंदु

- रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग की ओर से अधिसूचित यह सूची उन उपकरणों/प्रणालियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है, जिन्हें विकसित किया जा रहा है और अगले पांच वर्षों में इन्हें फर्म ऑर्डरों में रूपांतरित करने की संभावना है।
- इन हथियारों और प्लेटफार्मों को दिसंबर, 2022 से दिसंबर, 2027 तक क्रमिक रूप से स्वदेशी बनाने की योजना है।
- अब इन 101 वस्तुओं की खरीदारी **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020** के प्रावधानों के अनुरूप स्थानीय स्रोतों से की जाएगी।
- तीसरी सूची में अत्यधिक जटिल सिस्टम, सेंसर, हथियार और गोला-बारूद जैसे लाइट वेट टैंक, माउंटेड आर्टी गन सिस्टम, पिनाका MLRS के लिए गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज (GER) रॉकेट, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (NUH), नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल (NGOPV) आदि शामिल हैं।

संबंधित पहल:

- मई 2020 में, रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया था।
- आयुध निर्माणी बोर्डों का निगमीकरण
- डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज
- सृजन पोर्टल
- ई-बिज पोर्टल

स्रोत: PIB



# Weekly Current Affairs

## Science & Technology

IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना 'कदम' लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

- IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने देश का पहला मेड-इन-इंडिया पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना 'कदम' लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

- पॉलीसेंट्रिक घुटने को सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी (SBMT) और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है।
- SBMT DRDO के तहत पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा स्वदेशी चिकित्सा उपकरण विकास को सक्षम करने के लिए स्थापित किया गया था।
- मोबिलिटी इंडिया, बेंगलुरु में एक NGO, फिटमेंट और प्रशिक्षण की प्रक्रियाओं की देखरेख करने और उपयोगकर्ताओं के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर निर्माण और कदम को बाजार में ले जाएगा।
- इसे IIT मद्रास में TTK सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन रिसर्च एंड डिवाइस डेवलपमेंट (R2D2) की एक टीम द्वारा विकसित किया गया था, जिसने देश की पहली स्टैंडिंग व्हीलचेयर 'Arise' और NeoFly-NeoBolt, एक सक्रिय व्हीलचेयर को विकसित और व्यावसायीकरण किया।



स्रोत: इंडिया टुडे



## Sports

### ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा

#### चर्चा में क्यों?

- ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा।



#### प्रमुख बिंदु

- खेलों का मंचन मार्च 2026 में मेलबर्न, जिलॉन्ग, बेंडिगो, बल्लारेट और गिप्सलैंड सहित कई शहरों और क्षेत्रीय केंद्रों में किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक का अपना एथलीट गांव होगा।
- खेलों के लिए ट्वेंटी20 क्रिकेट सहित 16 खेलों की प्रारंभिक सूची आगे रखी गई है, जिसमें इस साल के अंत में और खेलों को शामिल किया जाएगा।
- यह छठी बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेलों का और दूसरी बार विक्टोरिया में मंचन किया है।

**नोट:** 2022 राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम, इंग्लैंड में आयोजित होने वाले हैं।

#### राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में:

- राष्ट्रमंडल खेल, जिसे अक्सर मैत्रीपूर्ण खेलों के रूप में जाना जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन है जिसमें राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के एथलीट शामिल होते हैं।
- यह आयोजन पहली बार 1930 में आयोजित किया गया था, और 1942 और 1946 को छोड़कर, तब से हर चार साल में होता है।

**स्रोत:** इंडियन एक्सप्रेस

### रोहित शर्मा T20 में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने

#### चर्चा में क्यों?

- रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं।





## प्रमुख बिंदु

- भारत और मुंबई इंडियंस के कप्तान ने पुणे में पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के IPL 2022 मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की।
- रोहित शर्मा T20 में 10 हजार रन पूरे करने वाले सातवें बल्लेबाज बन गए हैं।
- वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल 14,562 रन के साथ रन बनाने वालों की सूची में सबसे आगे हैं, इसके बाद पाकिस्तान के शोएब मलिक (11698), वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड (11474), ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच (10499), विराट कोहली (10379) और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर (10373) हैं।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

## नीदरलैंड ने चौथा FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीता

- **नीदरलैंड** ने दक्षिण अफ्रीका के पोटचेफस्ट्रूम में फाइनल में जर्मनी को हराकर अपना चौथा FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 खिताब जीता।
- इससे पहले, इंग्लैंड ने तीसरे स्थान के मैच में कांस्य पदक का दावा करने के लिए 2-2 से ड्रों के बाद शूट-आउट में भारत को हरा दिया।
- **2022 महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप** महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप का नौवां संस्करण है, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित द्विवार्षिक महिला अंडर -21 फील्ड हॉकी विश्व चैंपियनशिप है।



स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

## WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता

- भारत की दीपिका पल्लीकल कार्तिक और सौरव घोषाल ने मिश्रित युगल फाइनल में इंग्लैंड के एड्रियन वालर और एलिसन वाटर्स को हराकर स्कॉटलैंड के ग्लासग्लो में WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता।



- इसके अलावा दीपिका पल्लीकल ने अपनी जोड़ीदार जोशना चिनप्पा के साथ मिलकर महिला युगल का स्वर्ण भी जीता।

स्रोत: न्यूज़ऑनएयर

## Awards & Honours

फाल्गुनी नायर ने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता

चर्चा में क्यों?

- फाल्गुनी नायर, संस्थापक और CEO, नायका को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 नामित किया गया है।



प्रमुख बिंदु

- नायर अब 9 जून, 2022 को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड (WEOY) में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।
- EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर (EOY) अवार्ड्स एक वैश्विक व्यापार पुरस्कार कार्यक्रम है जो 60 देशों में मनाया जाता है।

स्रोत: बिजनेस टुडे

NMDC ने 80वें स्कोच शिखर सम्मेलन 2022 में दो पुरस्कार जीते

चर्चा में क्यों?

- भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक, **राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC)**, इस्पात मंत्रालय के तहत 80वें स्कोच शिखर सम्मेलन 2022 में एक स्वर्ण और एक रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



प्रमुख बिंदु

- स्कोच शिखर सम्मेलन का विषय 'स्टेट ऑफ BFSI एंड PSU' था।
- NMDC ने परियोजना 'NMDC ITI भांसी के माध्यम से दंतेवाड़ा जिले में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा' के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व की श्रेणी में गोल्ड अवार्ड और



ERP कार्यान्वयन के लिए 'परियोजना कल्पतरु' के लिए डिजिटल समावेशन श्रेणी में रजत पुरस्कार जीता।

**स्रोत: द हिंदू**

**असमिया कवि नीलमणि फूकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया**

**चर्चा में क्यों?**

- प्रख्यात असमिया कवि **नीलमणि फूकन** को **56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार** से सम्मानित किया गया, जिसका समारोह पहली बार असम में आयोजित किया गया था।



**प्रमुख बिंदु**

- असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और ज्ञानपीठ चयन बोर्ड की अध्यक्ष प्रतिभा रे ने 88 वर्षीय फूकन को ट्रॉफी, चेक और अन्य स्मृति चिन्ह सौंपे।
- उपन्यासकार बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य (1979) और ममोनी रईसम गोस्वामी (2000) के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले फूकन तीसरे असमिया हैं।
- फूकन ने अपने कविता संग्रह 'कोबीता' के लिए 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था।
- उन्हें 1990 में पद्म श्री और 2002 में साहित्य अकादमी फैलोशिप से सम्मानित किया गया था।
- **ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में:**
- ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को "साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान" के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है।

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**

**प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा**

**चर्चा में क्यों?**

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा, जिसे दिग्गज गायिका (लता मंगेशकर) की स्मृति में स्थापित किया गया था, जिनका इस साल फरवरी में निधन हो गया था।



## प्रमुख बिंदु

- मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान ने बताया कि पुरस्कार समारोह 24 अप्रैल को मुंबई के षण्मुखानंद हॉल में होगा।
- लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हर साल केवल एक व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिए पथप्रदर्शक, शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया है।

स्रोत: इंडिया टुडे

## उपराष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किए

- उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले एक संयुक्त समारोह में 44 प्रतिष्ठित कलाकारों (4 फेलो और 40 पुरस्कार विजेताओं) को वर्ष 2018 के लिए **संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एवं संगीत नाटक पुरस्कार** और वर्ष 2021 के लिए **ललित कला अकादमी** की 3 फेलोशिप तथा 20 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये।
- संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2018 के लिए प्रदर्शन कला (परफार्मिंग आर्ट) के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए चार फेलो - श्री जाकिर हुसैन, श्री जतिन गोस्वामी, डॉ. सोनल मानसिंह और श्री थिरुविदैमरुदुर कुप्पिया कल्याणसुंदरम - का चयन किया है।
- ललित कला अकादमी ने तीन उत्कृष्ट कलाकारों - श्री हिम्मत शाह, श्री ज्योति भट्ट और श्री श्याम शर्मा - को प्रतिष्ठित फेलोशिप से सम्मानित किया है।



## संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के बारे में:

- संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (अकादमी पुरस्कार) प्रदर्शन कला के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के साथ-साथ शिक्षकों और विद्वानों को भारत गणराज्य द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय सम्मान हैं।
- प्राप्तकर्ताओं का चयन अकादमी की सामान्य परिषद द्वारा किया जाता है, जिसमें इन विषयों के प्रतिष्ठित संगीतकार, नर्तक, थिएटर कलाकार और विद्वान शामिल होते हैं और भारत सरकार, राज्य सरकारों और भारतीय संघ के केंद्र शासित प्रदेशों के नामांकित व्यक्ति होते हैं।

स्रोत: PIB



## Appointments/Resignations

इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किये गए

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM)** के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया।



प्रमुख बिंदु

- लालपुरा, जिन्हें पहली बार पिछले साल सितंबर में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, को रोपड़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए दिसंबर में पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जो वह हार गए थे।

**राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) के बारे में:**

- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की।
- छह धार्मिक समुदाय, अर्थात; पूरे भारत में केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को भारत के राजपत्र में अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- स्थापना:** 17 मई 1993
- मुख्यालय:** नई दिल्ली

स्रोत: HT

विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला G20 समन्वयक होंगे

चर्चा में क्यों?

- विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को G20 शिखर सम्मेलन के लिए समन्वयक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिसकी मेजबानी भारत द्वारा 2023 में की जाएगी।



प्रमुख बिंदु

- 30 अप्रैल, 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले श्रृंगला 1 मई, 2022 को G20 समन्वयक के रूप में अपनी नई भूमिका का कार्यभार संभालेंगे।



- शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए यह एक नव निर्मित भूमिका है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल G20 के शेरपा बने रहेंगे।
- भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा।

## G-20 के बारे में:

- G-20 एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है।
- इसके सदस्य विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 80%, वैश्विक व्यापार का 75% और ग्रह की आबादी का 60% हिस्सा हैं।
- G-20 19 देशों और यूरोपीय संघ से बना है।
- 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूसी संघ, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और अमेरिका हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री चुने गए

### चर्चा में क्यों?

- पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के अध्यक्ष शहबाज शरीफ को एक हफ्ते के संवैधानिक संकट के बाद नेशनल असेंबली द्वारा पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में निर्विरोध चुना गया था, जो इमरान खान के अविश्वास मत हारने के बाद चरम पर था।



### प्रमुख बिंदु

- तीन बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज को 174 वोट मिले।
- उन्होंने तीन बार देश के सबसे अधिक आबादी वाले और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है।

स्रोत: HT



## प्रख्यात विद्वान-शिक्षाविद मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष नियुक्त

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, प्रख्यात विद्वान-शिक्षाविद, **डॉ मनोज सोनी** को **संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)** के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।



### प्रमुख बिंदु

- मनोज सोनी ने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है।
- इससे पहले, डॉ मनोज ने दो विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य किया।

### संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के बारे में:

- UPSC भारत सरकार के तहत सभी समूह 'A' अधिकारियों की भर्ती के लिए भारत की प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसी है।
- एजेंसी का चार्टर भारत के संविधान के भाग XIV द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसका शीर्षक संघ और राज्यों के तहत सेवाएं है।
- स्थापना:** 1 अक्टूबर 1926
- मुख्यालय:** नई दिल्ली

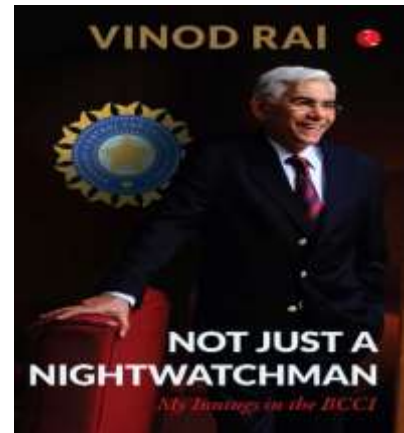
स्रोत: ET

## Books & Authors

## पूर्व CAG विनोद राय की किताब 'नॉट जस्ट ए नाइटवॉचमैन: माई इनिंग्स विद BCCI'

### चर्चा में क्यों?

- पूर्व CAG (नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त CoA (प्रशासक समिति) के प्रमुख विनोद राय ने "नॉट जस्ट ए नाइटवॉचमैन: माई इनिंग्स विद BCCI" नामक एक पुस्तक लिखी है।



## प्रमुख बिंदु

- किताब में विनोद राय ने BCCI में अपने 33 महीने के कार्यकाल का वर्णन किया है, जब उन्हें BCCI में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य प्रशासकों की समिति (CoA) के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था।
- पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशन इंडिया ने किया है।
- विनोद राय एक पूर्व IAS अधिकारी हैं जिन्होंने भारत के 11वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य किया।

## गीतांजलि श्री की 'टॉम्ब ऑफ सैंड' इंटरनेशनल बुकर शॉर्टलिस्ट पर पहला हिंदी उपन्यास

### चर्चा में क्यों?

- लेखक गीतांजलि श्री की उपन्यास 'टॉम्ब ऑफ सैंड' अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाली पहली हिंदी भाषा की कृति बन गई है।



### प्रमुख बिंदु

- डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित और जज द्वारा "लाउड एंड इर्रेसिसिबल नावेल" के रूप में वर्णित श्री की पुस्तक, प्रतिष्ठित 50,000 पाउंड साहित्यिक पुरस्कार के लिए दुनिया भर के पांच अन्य खिताबों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी, जो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित है।
- मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में जन्मी श्री तीन उपन्यासों और कई कहानी संग्रहों की लेखिका हैं, उनके काम का अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, सर्बियाई और कोरियाई में अनुवाद किया गया है।
- फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार के पूरक के रूप में, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हर साल एक एकल पुस्तक के लिए प्रदान किया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया जाता है।
- 2022 के विजेता की घोषणा 26 मई को लंदन में एक समारोह में की जाएगी।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस





## Important Days

## 14 अप्रैल, विश्व चगास रोग दिवस

## चर्चा में क्यों?

- चगास रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है।



## प्रमुख बिंदु

- 2022 का विषय 'चगास रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग' है।

## इतिहास:

- मई 2019 में WHO में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा प्राप्त अनुमोदन के बाद, यह पहली बार 14 अप्रैल, 2020 को मनाया गया था।
- इसका नाम ब्राजील के डॉक्टर कार्लोस रिबेरो जस्टिनियानो चागास के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 14 अप्रैल, 1909 को पहले मामले का निदान किया था।

**नोट:** विश्व चगास रोग दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व टीकाकरण सप्ताह, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व रक्त दाता दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह और विश्व एड्स दिवस के साथ चिह्नित 11 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है।

स्रोत: [who.int](http://who.int)

## 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग हत्याकांड

## चर्चा में क्यों?

- जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।



## प्रमुख बिंदु

- ब्रिटिश भारतीय सेना के लगभग 50 सैनिकों ने कर्नल रेजिनाल्ड डायर के कमांड में अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैशाखी के लिए एकत्र हुए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं।
- लोग, जिनमें से अधिकांश सिख थे, बैशाखी मनाने के लिए और दो स्वतंत्रता सेनानियों, सत्य पाल और डॉ सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन की निंदा करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे।
- ब्रिटिश सरकार के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 लोग मारे गए थे और 1,200 घायल हुए थे।

स्रोत: HT

## 10 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस

### चर्चा में क्यों?

- विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है।

### प्रमुख बिंदु

- विश्व होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी के संस्थापक, डॉ क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन की 267वीं जयंती को चिह्नित करने के लिए उनकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है।



### नोट:

- विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में तीन शीर्ष निकायों, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान द्वारा नई दिल्ली में 9 और 10 अप्रैल 2022 को दो दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- इस वैज्ञानिक सम्मेलन का विषय 'होमियोपैथी: पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस' था।

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

[Back To Top](#) ↑

